# उद्यमियों के लिए सोलर पालिसी में बदलाव कर सकती है सरकार

## इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमी महासम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- उद्यमियों से कहा-गुणवत्ता से समझौता नहीं करें, शासकीय खरीद में मिलेगी प्राथमिकता
- यूपी का एमएसएमई सेक्टर बन रहा देश की ताकत
- बुंदेलखंड-झांसी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार जल्द शुरू करेगी एयरपोर्ट

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित उद्यमी महासम्मेलन में महेश कुमार रस्तोगी व उनकी पत्नी अनिला रस्तोगी को सम्मानित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान • जागरण

जागरण संवाददाता, लखनऊ : छोटे और बड़े उद्यमियों को उद्योग चलाने में आसानी हो इसके लिए सरकार सोलर पालिसी में बदलाव कर सकती है। उद्यमियों की मांग पर पूर्ववर्ती नेट मीटरिंग व्यवस्था बहाल की जा सकती है। गुरुवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्यमी महासम्मेलन के उदघाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को उद्यमियों के साथ सोलर पालिसी पर बात करने को कहा। दरअसल नेट मीटरिंग की व्यवस्था कुछ समय पहले लागू थी, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया। आइआइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने अपने स्वागत भाषण में नेट मीटरिंग व्यवस्था फिर से बहाल करने की मांग की थी।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 700 उद्यमी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले यूपी में उद्यम के लिए माहौल न होने पर उद्यमी हतोत्साहित थे। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद अपने परंपरागत उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट करने के कार्यक्रम का परिणाम हम सबके सामने है। एक समय उत्तर प्रदेश की रैंकिंग ईज आफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर थी जो आज शीर्ष पर है। निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल और आनलाइन इन्सेंटिव प्लेटफार्म की चर्चा करते हुए कहा कि आज दुनिया के निवेशक प्रदेश की ओर देख रहे हैं। सरकार उद्यमियों के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। एमएसएमई उद्यमी उत्पादों की गुणवत्ता से समझौता नहीं करें। सरकार शासकीय खरीद में प्राथमिकता देगी। हमने टेक्नोलाजी को सुदृढ़ करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। हमारी सरकार कुछ शहरों तक नहीं, बल्कि उन इलाकों में भी उद्यम लगा रही है जो अब तक विकास से अपेक्षित थे। नोएडा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने में 46 साल लग गए, लेकिन बुंदेलखंड-झांसी औद्योगिक क्षेत्र में अभी से ही निवेशक आने लगे हैं। डिफेंस कारिडोर के तहत वहां कई बड़ी कंपनियां आ रही हैं और जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाने से गतिविधियों में और तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने सितंबर में नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो की सराहना करते हुए कहा कि जिस तरह ट्रेड शो के प्रति लोगों का रुझान था उसे देखते हुए सितंबर 2024 में और बड़ा ट्रेड शो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में इस तरह के ट्रेड शो कराने को कहा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मार्स आडिटोरियम में आयोजित ट्रांसफार्मिंग एमएसएमई टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड स्किल 48 से संबंधित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर से एमएसएमई स्टार्टअप्स उद्यमियों ने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव (एमएसएमई) अमित मोहन प्रसाद और आइआइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल व वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल मौजूद रहे।

## उद्यमियों ने कहा, औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड करे सरकार

- एमएसएमई सम्मेलन में उद्यमियों ने सरकार के सामने रखी कई मांगें
- उद्योग जिंदा रखने के लिए सोलर नेट मीटरिंग व्यवस्था बहाल हो

जासं, लखनऊ : सरकार एमएसएमई सेक्टर को देश के आर्थिक विकास की धुरी मान रही है और कह रही है कि यह प्राथमिकता वाला सेक्टर है। सरकार के दावों के बीच एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों की भी अपनी कई मांगें हैं। उद्यमियों का कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किए बिना एक ट्रिलियन डालर इकनामी के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा तभी सही मायने में आर्थिक विकास होगा।

आइआइए लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष विकास खन्ना का कहना कि यूपीसीडा एवं जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य ट्रस्ट के तहत औद्योगिक भूमि पर स्थापित उद्योगों में किसी तरह का बदलाव करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बैंक से लिमिट लेनी हो, लिमिट बढ़ानी हो, खाली जगह को किराये पर देना हो या ब्लड रिलेशन में देना हो, तो इसकी अनुमति के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सुगमता के लिए सरकार को चाहिए कि प्रदेश में लीज होल्ड की औद्योगिक भूमि को फ्री-होल्ड कर दिया जाए। इसके अलावा जिला प्राधिकरणों के विकास शुल्क काफी ज्यादा हैं और अलग अलग हैं। इसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है।

उद्यमी सूर्य प्रकाश हवेलिया का कहना है कि सरकार तो इंस्पेक्टर राज खत्म करने का दावा कर रही है, लेकिन कई विभागों में अभी भी कायम है। जीएसटी से औद्योगिक इकाईयों को प्राप्त बहुत कम राशि के नोटिसों के निस्तारण हेतु आनलाइन सिस्टम केंद्रीय जीएसटी की तरह किया जाना चाहिए। जीएसटी उद्यमियों को व्यक्तिगत पेशी पर नहीं बुलाया जाए। लखनऊ चैप्टर सोलर कमेटी के सदस्य चिंतन निगम का कहना है कि सोलर पालिसी में एमएसएमई उद्योगों को पूर्व की भांति नेट-मीटरिंग की सुविधा लागू की जाए। अभी जो व्यवस्था है उसमें उद्यमी नौ रुपये की बिजली खरीद रहे हैं और अपनी बिजली 3.58 पैसे में वापस दे रहे हैं।

### अन्य मांगें

परचेज पालिसी में भी बदलाव हो। 25 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से एवं 25 प्रतिशत सर्विस सेक्टर से कर दी जाए। भुगतान समय से नहीं होता। सरकारी संस्थानों में परचेज की पेमेंट के लिए टीआरईडीएस प्लेटफार्म का उपयोग हो। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओटीएस योजना को फिर से लागू कराया जाए।